



2026:AHC:58816

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या
- 2346 सन् 2026

शाजाद एवं अन्य

.... आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता : शुभम् श्रीवास्तव, सुनील कुमार श्रीवास्तव

विपक्षीगण के अधिवक्ता : जी.ए.,

न्यायालय संख्या - 72

माननीय जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत आवेदन वाद अपराध संख्या 42 सन् 2026, अंतर्गत धाराएँ 109(1), 336(2) बी.एन.एस. तथा धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम एवं 4/10 उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, थाना-मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर में अग्रिम जमानत की प्रार्थना के साथ इस निवेदन सहित प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की दशा में आवेदकगण को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्हें इस मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण प्राथमिकी में नामित नहीं थे तथा उनके नाम गिरफ्तार सह-अभियुक्त मोनिश के स्वीकारोक्ति कथन में प्रकाश में आए। घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई। सह-अभियुक्त शाजाद के विरुद्ध एक मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसमें उसे जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करेंगे तथा अन्वेषण अभिकरण अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उपस्थित होंगे। यह भी कहा गया कि यदि आवेदकगण को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, अन्वेषण में सहयोग करेंगे तथा जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेंगे।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया।
5. यह उल्लेखनीय है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा महत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से पलायन की संभावना तथा अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, और अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
6. वर्तमान प्रकरण में, अग्रिम जमानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन, आवेदकगण की भूमिका तथा प्रकरण के समस्त संगत तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का एक उपयुक्त मामला बनता है।
7. अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।
8. आवेदकगण- शाजाद एवं सुफियान को उपर्युक्त वाद अपराध में गिरफ्तारी की दशा में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार रु. 50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो-दो जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर, निम्नलिखित शर्तों सहित अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए :-
 - (i) आवेदकगण साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तथा संबंधित न्यायालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने के अतिरिक्त, नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे;
 - (ii) आवेदकगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;
 - (iii) आवेदकगण विचारण के दौरान सहयोग करेंगे तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।
 - (iv) आवेदकगण संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।
9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन को आवेदकगण को प्रदान की गई अग्रिम जमानत निरस्त कराए जाने हेतु उपयुक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2026
वीरेन्द्र

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"